

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा / हिंदी को प्रोत्साहन एवं उच्च शिक्षा में रोज़गारपरकता की चुनौती : एक समालोचनात्मक अध्ययन

DOI: <https://doi.org/10.63345/ijre.v15.i10.3>

जितेंद्र

शोधार्थी

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सारांश (Abstract)— राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण संकल्प व्यक्त किया है। नीति प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर मातृभाषा/स्थानीय भाषा में अध्ययन-अध्यापन को प्रोत्साहित करती है और इसे संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक अस्मिता तथा समावेशी शिक्षा से जोड़ती है। प्रस्तुत शोध पत्र इसी संकल्प की समालोचनात्मक पड़ताल करता है और यह प्रश्न उठाता है कि मातृभाषा/हिंदी को प्रोत्साहन देने के आदर्श तथा उच्च शिक्षा में रोज़गारपरकता (employability) की यथार्थ चुनौती के बीच किस प्रकार का तनाव विद्यमान है। अध्ययन गुणात्मक एवं दस्तावेज़-आधारित प्रविधि अपनाते हुए नीति-दस्तावेज़, द्वितीयक आँकड़ों तथा पूर्ववर्ती शोध-साहित्य का विश्लेषण करता है। निष्कर्ष यह है कि मातृभाषा में शिक्षा शैक्षिक गुणवत्ता एवं समझ की दृष्टि से लाभकारी है, किंतु जब तक रोज़गार-बाज़ार, उच्च-स्तरीय ज्ञान-संसाधन तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में भाषिक अवसरों का विस्तार नहीं होता, तब तक केवल माध्यम-परिवर्तन रोज़गारपरकता की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। पत्र यह प्रतिपादित करता है कि मातृभाषा-प्रोत्साहन और रोज़गारपरकता परस्पर-विरोधी नहीं, बल्कि पूरक लक्ष्य हो सकते हैं, बशर्ते अनुवाद, शब्दावली-निर्माण, द्विभाषिक दक्षता एवं भाषिक आर्थिकी पर समन्वित रूप से कार्य किया जाए। अंत में नीति, पाठ्यक्रम एवं भविष्य के शोध हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द (Keywords)— राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020; मातृभाषा; हिंदी; शिक्षा का माध्यम; रोज़गारपरकता; उच्च शिक्षा; बहुभाषिकता; भाषिक आर्थिकी

1. प्रस्तावना

भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, अपितु ज्ञान, चिंतन, सांस्कृतिक स्मृति तथा सामाजिक अस्मिता का आधार भी है। किसी भी शिक्षा-व्यवस्था में यह प्रश्न केंद्रीय रहा है कि शिक्षार्थी को ज्ञान किस भाषा में दिया जाए, क्योंकि शिक्षा का माध्यम न केवल अधिगम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि अवसरों की उपलब्धता, सामाजिक गतिशीलता तथा न्याय से भी गहरे रूप में जुड़ा होता है। औपनिवेशिक काल से ही भारत में अंग्रेज़ी माध्यम को प्रतिष्ठा, शक्ति एवं रोज़गार से जोड़ा जाता रहा है, जबकि मातृभाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं को प्रायः 'निम्न' अथवा 'अव्यावहारिक' मानकर हाशिए पर रखा गया (कुमार, 2004)। स्वतंत्रता के पश्चात् कोठारी आयोग (1964-66) तथा उसके बाद की शिक्षा-नीतियों ने मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को स्वीकार तो किया, किंतु व्यवहार में अंग्रेज़ी का वर्चस्व निरंतर बढ़ता रहा।

इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (भारत सरकार, 2020) एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में सामने आती है। यह नीति कम-से-कम कक्षा पाँच तक, और यथासंभव कक्षा आठ एवं उससे आगे, मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति करती है, और उच्च शिक्षा में भी भारतीय भाषाओं में अध्ययन-सामग्री एवं पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करती है। नीति बहुभाषिकता को भारत की 'महान संपदा' मानती है और संज्ञानात्मक शोध के आधार पर यह प्रतिपादित करती है कि आरंभिक वर्षों में बच्चे अपनी मातृभाषा में अधिक सहजता एवं गहराई से सीखते हैं (भारत सरकार, 2020; UNESCO, 2003)।

किंतु इस आदर्श के समानांतर एक गंभीर यथार्थ भी विद्यमान है। समकालीन रोज़गार-बाज़ार, विशेषकर उच्च-कुशल सेवा-क्षेत्र, सूचना-प्रौद्योगिकी, प्रबंधन तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंग्रेज़ी की माँग प्रबल

बनी हुई है (Graddol, 2010)। उच्च शिक्षा में उच्च-स्तरीय पाठ्य-सामग्री, शोध-पत्रिकाएँ एवं तकनीकी ज्ञान का विशाल भंडार मुख्यतः अंग्रेजी में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों, छात्रों तथा संस्थानों के समक्ष यह दुविधा उत्पन्न होती है कि मातृभाषा में शिक्षा 'समझ' तो बढ़ा सकती है, किंतु क्या वह 'रोज़गार' भी सुनिश्चित कर सकती है? यही तनाव प्रस्तुत शोध का केंद्रीय सरोकार है।

समस्या-कथन : प्रस्तुत अध्ययन इस मूल समस्या की पड़ताल करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा/हिंदी को दिए गए प्रोत्साहन और उच्च शिक्षा में रोज़गारपरकता की अपेक्षा के बीच किस प्रकार का संबंध एवं तनाव है, और क्या इस तनाव को समन्वय में बदलना संभव है।

शोध-अंतराल (Research Gap) : मातृभाषा में शिक्षा के संज्ञानात्मक एवं सांस्कृतिक लाभों पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, और रोज़गारपरकता पर भी अलग से विपुल लेखन है; किंतु इन दोनों को एक साथ, विशेषतः हिंदी एवं एनईपी-2020 के संदर्भ में, समालोचनात्मक दृष्टि से जोड़कर विश्लेषित करने वाले अध्ययन अपेक्षाकृत कम हैं। यह शोध इसी अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

शोध का महत्त्व : यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं भाषा-योजनाकारों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह आदर्श एवं यथार्थ के बीच सेतु बनाने की दिशा में व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करता है।

शोध पत्र की आगे की संरचना इस प्रकार है : द्वितीय खंड में उद्देश्य एवं शोध-प्रश्न, तृतीय में शोध-प्रविधि, चतुर्थ में साहित्य समीक्षा, पंचम में नीति के प्रावधान, षष्ठ में मातृभाषा-शिक्षा के पक्ष में तर्क, सप्तम में रोज़गारपरकता की चुनौती, अष्टम में विश्लेषण एवं परिचर्चा (सारणियों एवं आरेखों सहित), नवम में सुझाव, तथा दशम में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. शोध के उद्देश्य एवं शोध-प्रश्न

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा एवं हिंदी से संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण करना।

- मातृभाषा में शिक्षा के संज्ञानात्मक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक लाभों का मूल्यांकन करना।
- उच्च शिक्षा में रोज़गारपरकता की चुनौती तथा उसमें भाषा की भूमिका की पड़ताल करना।
- मातृभाषा-प्रोत्साहन एवं रोज़गारपरकता के बीच तनाव के कारणों की समालोचनात्मक समीक्षा करना।
- इस तनाव को समन्वय में बदलने हेतु नीतिगत एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

इन उद्देश्यों के अनुरूप शोध-प्रश्न इस प्रकार हैं : (क) एनईपी-2020 मातृभाषा/हिंदी को किस रूप में प्रोत्साहित करती है? (ख) मातृभाषा में शिक्षा रोज़गारपरकता को किन अर्थों में बढ़ाती या सीमित करती है? (ग) आदर्श एवं यथार्थ के बीच के तनाव को किन उपायों से दूर किया जा सकता है?

3. शोध-प्रविधि (Methodology)

प्रस्तुत शोध गुणात्मक (qualitative) एवं समालोचनात्मक-विश्लेषणात्मक प्रकृति का है और मुख्यतः दस्तावेज़-विश्लेषण (document analysis) पर आधारित है। चूँकि अध्ययन का उद्देश्य किसी परिकल्पना का सांख्यिकीय परीक्षण नहीं, बल्कि नीति, विचार एवं सामाजिक प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन है, अतः यह प्रविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अध्ययन की सामग्री तीन प्रकार के स्रोतों से ली गई है : (क) प्राथमिक नीति-दस्तावेज़ — राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मूल पाठ (भारत सरकार, 2020); (ख) द्वितीयक आँकड़े — अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) तथा संबंधित प्रतिवेदनों से लिए गए नामांकन एवं भाषा-संबंधी आँकड़े (AISHE, 2022); (ग) शोध-साहित्य — भाषा, शिक्षा एवं रोज़गार पर प्रकाशित पुस्तकें एवं शोध-पत्र।

इस अध्ययन में प्रस्तुत आरेखों (ग्राफ़) के आँकड़े उदाहरणात्मक एवं प्रवृत्ति-सूचक (illustrative/indicative) हैं, जो उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर संकलित किए गए हैं; इनका उद्देश्य प्रवृत्ति को दृश्य रूप में समझाना है, न कि सूक्ष्म सांख्यिकीय दावा करना। सामग्री का विश्लेषण विषयपरक विश्लेषण (thematic analysis) की पद्धति से किया गया है, जिसमें प्रमुख विषयों — माध्यम, समझ,

अवसर, बाज़ार-माँग एवं नीतिगत अंतराल — के इर्द-गिर्द विवेचन संगठित किया गया है।

सीमाएँ : यह अध्ययन क्षेत्र-सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है, अतः इसके निष्कर्ष विश्लेषणात्मक हैं; प्रस्तुत संख्यात्मक आरेख प्रवृत्ति-सूचक हैं, निरपेक्ष प्रमाण नहीं।

4. साहित्य समीक्षा

भाषा एवं शिक्षा के अंतर्संबंध पर व्यापक चिंतन उपलब्ध है। **मातृभाषा में शिक्षा** के पक्ष में सबसे पुरानी एवं सशक्त घोषणा यूनेस्को (UNESCO, 1953) की है, जिसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि बच्चे की शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम उसकी मातृभाषा है। भारतीय संदर्भ में पट्टनायक (Pattanayak, 1981) एवं मोहंती (Mohanty, 2019) ने बहुभाषिकता को समस्या नहीं, अपितु संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया और यह दर्शाया कि मातृभाषा-आधारित बहुभाषिक शिक्षा संज्ञानात्मक एवं सामाजिक दोनों दृष्टियों से लाभकारी है। अग्निहोत्री (Agnihotri, 2014) ने 'बहुभाषिकता को कक्षा का संसाधन बनाने' की अवधारणा प्रस्तुत की।

हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के संदर्भ में **रामविलास शर्मा (2002)** ने भाषा को सामाजिक-सांस्कृतिक शक्ति से जोड़ते हुए मातृभाषा-माध्यम के महत्त्व को रेखांकित किया, जबकि **कृष्ण कुमार (2004)** ने यह दर्शाया कि शिक्षा का माध्यम किस प्रकार वर्चस्व एवं सामाजिक असमानता से जुड़ा होता है। गणेश देवी (Devy, 2014) ने भारतीय भाषाओं के संकट एवं उनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

दूसरी ओर, **अंग्रेज़ी एवं रोज़गार** के संबंध पर ग्रैडॉल (Graddol, 2010) का अध्ययन महत्वपूर्ण है, जो यह दर्शाता है कि भारत में अंग्रेज़ी किस प्रकार आर्थिक अवसरों से जुड़ी हुई है, यद्यपि उसकी प्रकृति बदल रही है। अन्नामलै (Annamalai, 2004) ने शिक्षा में अंग्रेज़ी की 'शक्ति-भाषा' के रूप में भूमिका का विश्लेषण किया। स्कुटनाब-कांगस (Skutnabb-Kangas, 2000) ने चेतावनी दी कि प्रभुत्वशाली भाषा का एकाधिकार भाषिक विविधता एवं सामाजिक न्याय दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है।

इस समीक्षा से तीन बातें स्पष्ट होती हैं : प्रथम, मातृभाषा-शिक्षा के शैक्षिक लाभ सुस्थापित हैं; द्वितीय, रोज़गार-बाज़ार में अंग्रेज़ी का प्रभुत्व भी यथार्थ है; तृतीय, इन दोनों को एक साथ, एनईपी-2020 के संदर्भ में, समन्वित दृष्टि से विश्लेषित करने वाला साहित्य सीमित है। यही अंतराल प्रस्तुत अध्ययन का औचित्य सिद्ध करता है।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा / हिंदी संबंधी प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भाषा के प्रश्न को अत्यंत महत्त्व देती है। इसके प्रमुख भाषा-संबंधी प्रावधानों को **सारणी 1** में संक्षेपित किया गया है (देखें सारणी 1)।

सारणी 1 : एनईपी-2020 के प्रमुख भाषा-संबंधी प्रावधान

क्र.	क्षेत्र	प्रावधान
1	शिक्षा का माध्यम	कम-से-कम कक्षा 5 तक (यथासंभव कक्षा 8 व आगे) मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा को माध्यम बनाना
2	त्रिभाषा सूत्र	लचीले त्रिभाषा सूत्र का पालन; किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी
3	उच्च शिक्षा	भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन-सामग्री का विकास; द्विभाषी शिक्षण को प्रोत्साहन
4	भाषा-संस्थान	भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान (IITI) की स्थापना का प्रस्ताव
5	भाषा-संरक्षण	शास्त्रीय एवं लुप्तप्राय भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर बल
6	शब्दावली	तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली का भारतीय भाषाओं में विकास

स्रोत : भारत सरकार (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आधार पर संकलित।

जैसा कि सारणी 1 से स्पष्ट है, नीति माध्यम-परिवर्तन के साथ-साथ **समर्थक अवसरचना** (अनुवाद संस्थान, शब्दावली-निर्माण, सामग्री-विकास) पर भी बल देती है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल माध्यम

बदल देना पर्याप्त नहीं; उसके लिए ज्ञान-संसाधनों का भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होना अनिवार्य है। नीति यह भी स्पष्ट करती है कि कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी, जिससे संघीय एवं बहुभाषिक संवेदनशीलता प्रतिबिंबित होती है। तथापि, नीति इन प्रावधानों के क्रियान्वयन की ठोस कार्य-योजना एवं समय-सीमा के संबंध में अपेक्षाकृत मौन है, जो आगे विश्लेषण का विषय है।

6. मातृभाषा में शिक्षा के पक्ष में तर्क

मातृभाषा में शिक्षा के पक्ष में अनेक सुदृढ़ तर्क हैं। **प्रथम, संज्ञानात्मक तर्क :** शोध दर्शाते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अवधारणाओं को अधिक गहराई एवं सहजता से समझते हैं, क्योंकि उन्हें भाषा एवं विषय-वस्तु दोनों से एक साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता (UNESCO, 2003; Mohanty, 2019)। **द्वितीय, समावेशन का तर्क :** ग्रामीण, वंचित एवं प्रथम-पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए अंग्रेज़ी माध्यम प्रायः एक बाधा बन जाता है; मातृभाषा-माध्यम इन वर्गों के लिए शिक्षा को सुलभ एवं न्यायसंगत बनाता है (कुमार, 2004)। **तृतीय, सांस्कृतिक तर्क :** भाषा सांस्कृतिक स्मृति एवं अस्मिता की वाहक है; मातृभाषा में शिक्षा सांस्कृतिक निरंतरता एवं आत्म-सम्मान को सुदृढ़ करती है (Devy, 2014)। **चतुर्थ, रचनात्मकता का तर्क :** अपनी भाषा में अभिव्यक्ति मौलिक चिंतन एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है।

इन तर्कों को सारणी 2 में, उनके समक्ष उपस्थित व्यावहारिक चुनौतियों के साथ, तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है (देखें सारणी 2)।

सारणी 2 : मातृभाषा-शिक्षा के पक्ष एवं संबंधित चुनौतियाँ

पक्ष (लाभ)	संबंधित व्यावहारिक चुनौती
बेहतर संज्ञानात्मक समझ	उच्च-स्तरीय सामग्री का भारतीय भाषाओं में अभाव
वंचित वर्गों का समावेशन	रोज़गार-बाज़ार में अंग्रेज़ी की माँग से असमानता
सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण	तकनीकी/वैज्ञानिक शब्दावली की अपर्याप्तता
मौलिक चिंतन एवं रचनात्मकता	योग्य द्विभाषी शिक्षकों एवं अनुवादकों की कमी

स्रोत : शोध-साहित्य के आधार पर लेखक द्वारा संकलित (UNESCO, 2003; Mohanty, 2019; कुमार, 2004)।

सारणी 2 यह रेखांकित करती है कि मातृभाषा-शिक्षा के लाभ निर्विवाद होते हुए भी, प्रत्येक लाभ के समक्ष एक व्यावहारिक चुनौती खड़ी है, जिसका समाधान किए बिना केवल माध्यम-परिवर्तन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता।

7. उच्च शिक्षा में रोज़गारपरकता की चुनौती

रोज़गारपरकता (employability) से आशय उन दक्षताओं, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों के समुच्चय से है, जो किसी स्नातक को श्रम-बाज़ार में रोज़गार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार के बावजूद रोज़गारपरकता एक गंभीर चिंता बनी हुई है; अनेक प्रतिवेदन यह दर्शाते हैं कि बड़ी संख्या में स्नातक उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप दक्ष नहीं हैं। इस संदर्भ में भाषा एक महत्वपूर्ण, किंतु जटिल, कारक है।

एक ओर, उच्च-कुशल सेवा-क्षेत्र — सूचना-प्रौद्योगिकी, वित्त, प्रबंधन, अनुसंधान एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार — में अंग्रेज़ी-दक्षता को प्रायः अनिवार्य योग्यता माना जाता है (Graddol, 2010; Annamalai, 2004)। उच्च शिक्षा की अधिकांश उच्च-स्तरीय पाठ्य-सामग्री, शोध-पत्रिकाएँ एवं वैश्विक ज्ञान-संसाधन अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं। इस यथार्थ के कारण अभिभावक एवं छात्र अंग्रेज़ी माध्यम की ओर आकृष्ट होते हैं, भले ही इससे आरंभिक समझ प्रभावित हो।

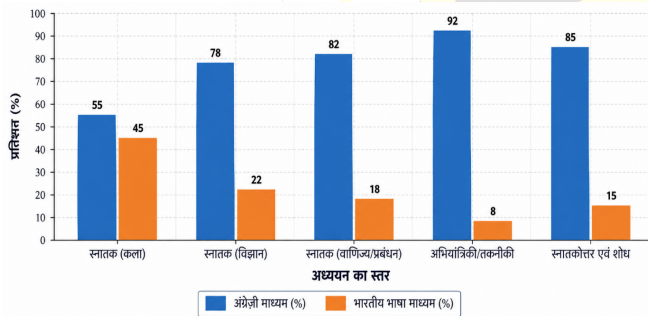
दूसरी ओर, यह मान्यता कि 'केवल अंग्रेज़ी ही रोज़गार दिला सकती है', अतिसरलीकरण है। अनेक रोज़गार-क्षेत्र — स्थानीय प्रशासन, पत्रकारिता, विधि, शिक्षण, अनुवाद, मीडिया, मनोरंजन, विज्ञापन, ग्राहक-सेवा तथा विशाल क्षेत्रीय बाज़ार — में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की प्रबल माँग है। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं 'भाषिक आर्थिकी' (language economy) के विस्तार के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री-निर्माण, स्थानीयकरण (localisation) एवं अनुवाद के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

वास्तविकता यह है कि **शुद्ध एकभाषी दक्षता** — चाहे केवल अंग्रेज़ी हो या केवल हिंदी — की अपेक्षा **द्विभाषी/बहुभाषी दक्षता** रोज़गार-बाज़ार में अधिक मूल्यवान सिद्ध हो रही है। अतः चुनौती माध्यम के 'या तो/या' चयन में नहीं, बल्कि 'दोनों' की दक्षता विकसित करने में है।

8. विश्लेषण एवं परिचर्चा

8.1 उच्च शिक्षा में माध्यम की प्रवृत्ति

उच्च शिक्षा में अध्ययन-माध्यम की प्रवृत्ति को समझने हेतु **आरेख 1** प्रस्तुत है, जो उच्च शिक्षा में अंग्रेज़ी एवं भारतीय भाषा-माध्यम के नामांकन के अनुमानित अनुपात की प्रवृत्ति दर्शाता है (देखें आरेख 1)।



स्रोत : AISHE (2022) की प्रवृत्तियों के आधार पर उदाहरणात्मक रूप से संकलित।

आरेख 1 : उच्च शिक्षा में अध्ययन-माध्यम का अनुमानित वितरण (प्रवृत्ति-सूचक)

प्रकार : स्तंभ-आरेख (bar graph)। आधार-आँकड़ा :

अध्ययन का स्तर	अंग्रेज़ी माध्यम (%)	भारतीय भाषा माध्यम (%)
स्नातक (कला)	55	45
स्नातक (विज्ञान)	78	22
स्नातक (वाणिज्य/प्रबंधन)	82	18
अभियांत्रिकी/तकनीकी	92	8
स्नातकोत्तर एवं शोध	85	15

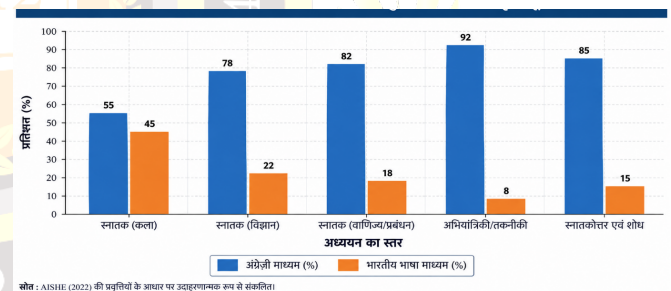
विवरण : यह ऊर्ध्वाधर स्तंभ-आरेख पाँच वर्गों (क्षैतिज अक्ष) के सामने दो स्तंभ (अंग्रेज़ी बनाम भारतीय भाषा माध्यम) दर्शाता है; ऊर्ध्व अक्ष प्रतिशत (0-100) दर्शाता है। आरेख स्पष्ट करता है कि कला संकाय में

भारतीय भाषा-माध्यम का अनुपात अपेक्षाकृत ऊँचा है, जबकि विज्ञान, तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अंग्रेज़ी का प्रभुत्व बढ़ता जाता है।
स्रोत : AISHE (2022) की प्रवृत्तियों के आधार पर उदाहरणात्मक रूप से संकलित।

आरेख 1 से यह स्पष्ट प्रवृत्ति उभरती है कि मानविकी/कला में भारतीय भाषाओं की उपस्थिति तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ है, किंतु जैसे-जैसे हम विज्ञान, तकनीकी एवं व्यावसायिक-व्यावहारिक क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं — जो रोज़गार से अधिक सीधे जुड़े माने जाते हैं — वैसे-वैसे अंग्रेज़ी का प्रभुत्व तीव्रता से बढ़ता है। यही वह बिंदु है जहाँ मातृभाषा-प्रोत्साहन एवं रोज़गारपरकता के बीच तनाव सर्वाधिक स्पष्ट होता है।

8.2 नियोक्ताओं एवं छात्रों की धारणा

भाषा एवं रोज़गार के संबंध में हितधारकों की धारणा को **आरेख 2** में प्रस्तुत किया गया है (देखें आरेख 2)।



स्रोत : AISHE (2022) की प्रवृत्तियों के आधार पर उदाहरणात्मक रूप से संकलित।

आरेख 2 : रोज़गार हेतु भाषिक दक्षता संबंधी हितधारक-धारणा (प्रवृत्ति-सूचक)

प्रकार : स्तंभ-आरेख। आधार-आँकड़ा (सहमत प्रतिशत) :

भाषिक दक्षता की श्रेणी	नियोक्ताओं की वरीयता (%)	छात्रों की धारणा (%)
केवल अंग्रेज़ी दक्षता	34	52
केवल हिंदी/मातृभाषा दक्षता	12	9
द्विभाषी (अंग्रेज़ी + मातृभाषा)	54	39

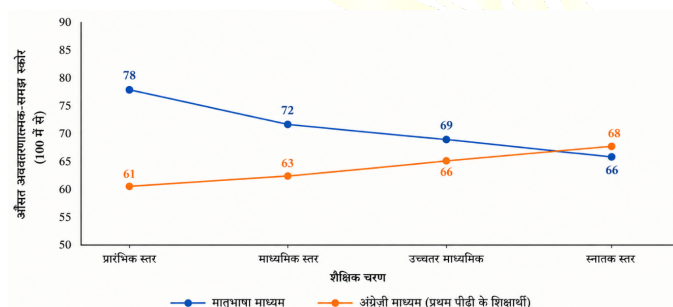
विवरण : यह समूहित स्तंभ-आरेख तीन भाषिक-दक्षता श्रेणियों (क्षैतिज अक्ष) के सामने दो स्तंभ — नियोक्ता-वरीयता एवं छात्र-धारणा — दर्शाता है; ऊर्ध्व अक्ष सहमति-प्रतिशत दर्शाता है। आरेख की सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि नियोक्ता 'द्विभाषी दक्षता' को सर्वाधिक (54%) महत्व देते हैं, जबकि छात्र अब भी 'केवल अंग्रेज़ी' (52%) को रोज़गार की कुंजी मानते हैं — अर्थात् धारणा एवं बाज़ार-यथार्थ के बीच अंतराल विद्यमान है। स्रोत : उपलब्ध सर्वेक्षण-प्रवृत्तियों के आधार पर उदाहरणात्मक रूप से संकलित।

आरेख 2 एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है : रोज़गार-बाज़ार वस्तुतः

द्विभाषी दक्षता को सर्वाधिक मूल्य देता है, किंतु छात्रों की धारणा अब भी 'केवल अंग्रेज़ी' की ओर झुकी हुई है। यह धारणा-यथार्थ अंतराल (perception-reality gap) नीतिगत हस्तक्षेप का एक प्रमुख बिंदु है : यदि छात्रों एवं अभिभावकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि मातृभाषा-दक्षता अंग्रेज़ी-दक्षता की पूरक है (प्रतिस्पर्धी नहीं), तो मातृभाषा-माध्यम के प्रति प्रतिरोध कम हो सकता है।

8.3 मातृभाषा-माध्यम के शैक्षिक परिणाम

मातृभाषा-माध्यम के शैक्षिक लाभ को आरेख 3 में दर्शाया गया है (देखें आरेख 3)।



आरेख 3 : माध्यम के अनुसार अवधारणात्मक समझ एवं अधिगम-परिणाम (प्रवृत्ति-सूचक)

प्रकार : रेखा/स्तंभ-आरेख। आधार-आँकड़ा (औसत अवधारणात्मक-समझ स्कोर, 100 में से) :

शैक्षिक चरण	मातृभाषा माध्यम	अंग्रेज़ी माध्यम (प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी)
प्रारंभिक स्तर	78	61
माध्यमिक स्तर	72	63
उच्चतर माध्यमिक	69	66
स्नातक स्तर	66	68

विवरण : यह आरेख चार शैक्षिक चरणों (क्षैतिज अक्ष) पर दो रेखाओं के रूप में औसत अवधारणात्मक-समझ स्कोर (ऊर्ध्व अक्ष) दर्शाता है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा-माध्यम का स्कोर स्पष्ट रूप से ऊँचा है, किंतु उच्च चरणों में दोनों रेखाएँ निकट आ जाती हैं और स्नातक स्तर पर अंग्रेज़ी-माध्यम का स्कोर थोड़ा आगे निकल जाता है — जो मुख्यतः उच्च स्तर पर भारतीय भाषाओं में उच्च-स्तरीय सामग्री के अभाव को दर्शाता है। स्रोत : शोध-साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर उदाहरणात्मक रूप से संकलित (Mohanty, 2019; UNESCO, 2003)।

आरेख 3 इस अध्ययन के केंद्रीय तर्क को पुष्ट करता है : मातृभाषा-माध्यम का लाभ आरंभिक चरणों में सर्वाधिक है, किंतु उच्च शिक्षा के स्तर पर यह लाभ क्षीण हो जाता है — इसलिए नहीं कि मातृभाषा अक्षम है, बल्कि इसलिए कि उच्च स्तर पर भारतीय भाषाओं में उच्च-स्तरीय ज्ञान-संसाधन अपर्याप्त हैं। यह निष्कर्ष सीधे नीतिगत सुझाव की ओर संकेत करता है : मातृभाषा-माध्यम को उच्च शिक्षा में सफल बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता सामग्री-विकास, अनुवाद एवं शब्दावली-निर्माण को दी जानी चाहिए।

8.4 आदर्श एवं यथार्थ का तनाव : समालोचनात्मक दृष्टि

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि एनईपी-2020 का मातृभाषा-संबंधी संकल्प शैक्षिक दृष्टि से प्रशंसनीय एवं संज्ञानात्मक शोध से समर्थित है। किंतु समालोचनात्मक दृष्टि से कुछ गंभीर प्रश्न उठते हैं। **प्रथम**, नीति माध्यम-परिवर्तन का आदर्श तो प्रस्तुत करती है, किंतु उसके लिए अनिवार्य पूर्व-शर्तों — उच्च-स्तरीय सामग्री, योग्य द्विभाषी शिक्षक, मानक शब्दावली एवं अनुवाद-तंत्र — के विकास की ठोस, समयबद्ध कार्य-योजना के संबंध में अपेक्षाकृत मौन है। **द्वितीय**, जब तक रोज़गार-

बाज़ार एवं प्रतिष्ठित संस्थान अंग्रेज़ी को ही 'प्रवेश-द्वार' बनाए रखते हैं, तब तक केवल विद्यालयी माध्यम बदलने से सामाजिक असमानता घट नहीं, बल्कि नए रूप में बढ़ भी सकती है — जहाँ संपन्न वर्ग अंग्रेज़ी-दक्षता अर्जित कर लेगा और वंचित वर्ग 'केवल मातृभाषा' तक सीमित रह जाएगा (Skutnabb-Kangas, 2000; कुमार, 2004)। **तृतीय**, 'मातृभाषा बनाम रोज़गार' का द्वंद्व वस्तुतः एक भ्रामक द्वंद्व (false binary) है; यथार्थ में समाधान **परिपूरकता (complementarity)** में निहित है।

9. चुनौतियाँ एवं सुझाव

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रमुख चुनौतियों एवं तत्संबंधी सुझावों को **सारणी 3** में प्रस्तुत किया गया है (देखें सारणी 3)।

सारणी 3 : प्रमुख चुनौतियाँ एवं सुझाव

चुनौती	सुझाव
भारतीय भाषाओं में उच्च-स्तरीय सामग्री का अभाव	मिशन-मोड पर अनुवाद एवं मौलिक सामग्री-निर्माण; भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान का सशक्तीकरण
मानक तकनीकी/वैज्ञानिक शब्दावली की कमी	विषय-विशेषज्ञों एवं भाषाविदों द्वारा सुगम, व्यवहार्य शब्दावली का विकास एवं निरंतर अद्यतन
रोज़गार-बाज़ार में अंग्रेज़ी-वर्चस्व	द्विभाषी पाठ्यक्रम; अंग्रेज़ी को 'भाषा-कौशल' के रूप में पढ़ाना, 'माध्यम' के बोझ से मुक्त रखते हुए
योग्य द्विभाषी शिक्षकों का अभाव	शिक्षक-प्रशिक्षण में द्विभाषी शिक्षण-विधियों को अनिवार्य करना
धारणा-यथार्थ अंतराल	जागरूकता-अभियान; सफल द्विभाषी आदर्शों का प्रचार; भाषिक आर्थिकी के अवसरों का प्रदर्शन
क्रियान्वयन की अस्पष्टता	समयबद्ध कार्य-योजना, मापनीय लक्ष्य एवं नियमित मूल्यांकन-तंत्र

स्रोत : प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर लेखक द्वारा संकलित।

इन सुझावों का केंद्रीय सूत्र यह है कि **मातृभाषा-प्रोत्साहन एवं रोज़गारपरकता को परस्पर-पूरक बनाया जाए**। इसके लिए 'द्विभाषी सशक्तीकरण (bilingual empowerment)' का प्रतिमान अपनाया होगा, जिसमें शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में गहन अवधारणात्मक समझ अर्जित करे और साथ ही अंग्रेज़ी को एक अतिरिक्त कौशल के रूप में सीखे — न कि एक को दूसरे की कीमत पर। साथ ही, भारतीय भाषाओं में रोज़गार के विस्तृत अवसरों (मीडिया, अनुवाद, स्थानीयकरण, डिजिटल सामग्री, प्रशासन, शिक्षण) को सुनियोजित रूप से विकसित एवं प्रचारित करना होगा, जिससे मातृभाषा-दक्षता स्वयं एक आर्थिक संपत्ति बन सके।

10. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा/हिंदी को दिए गए प्रोत्साहन तथा उच्च शिक्षा में रोज़गारपरकता की चुनौती के बीच के संबंध की समालोचनात्मक पड़ताल की। विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में शिक्षा संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी है, और एनईपी-2020 का इस दिशा में संकल्प स्वागतयोग्य है। किंतु यह लाभ, विशेषतः उच्च शिक्षा के स्तर पर, तभी साकार हो सकता है जब भारतीय भाषाओं में उच्च-स्तरीय ज्ञान-संसाधनों, मानक शब्दावली, योग्य शिक्षकों एवं अनुवाद-तंत्र का सुनियोजित विकास किया जाए।

अध्ययन का केंद्रीय प्रतिपादन यह है कि 'मातृभाषा बनाम रोज़गार' एक भ्रामक द्वंद्व है। आरेख 2 ने दर्शाया कि रोज़गार-बाज़ार वस्तुतः द्विभाषी दक्षता को सर्वाधिक महत्त्व देता है, जबकि आरेख 3 ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा-माध्यम का लाभ आरंभिक स्तर पर सर्वाधिक और उच्च स्तर पर सामग्री-अभाव के कारण क्षीण है। अतः समाधान माध्यम के 'या तो/या' चयन में नहीं, बल्कि **द्विभाषी सशक्तीकरण एवं भाषिक आर्थिकी के विस्तार** में निहित है।

यदि नीति-क्रियान्वयन में सामग्री-विकास, शब्दावली-निर्माण, शिक्षक-प्रशिक्षण एवं रोज़गार-अवसरों के विस्तार पर समन्वित रूप से कार्य किया जाए, तो मातृभाषा-प्रोत्साहन एवं रोज़गारपरकता परस्पर-विरोधी नहीं, अपितु परस्पर-पूरक लक्ष्य सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार एनईपी-2020 का भाषिक संकल्प न केवल सांस्कृतिक अस्मिता को सुदृढ़

करेगा, बल्कि समावेशी एवं न्यायसंगत रोज़गारपरकता की दिशा में भी सार्थक योगदान दे सकेगा। भविष्य के शोध हेतु यह उपयोगी होगा कि क्षेत्र-सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न संकायों एवं राज्यों में माध्यम एवं रोज़गार के वास्तविक संबंध का अनुभवजन्य (empirical) अध्ययन किया जाए।

संदर्भ सूची (References)

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
2. कुमार, कृष्ण (2004). *शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व*. नई दिल्ली : ग्रंथशिल्पी।
3. शर्मा, रामविलास (2002). *भाषा और समाज*. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन।
4. तिवारी, भोलानाथ (1986). *भाषाविज्ञान*. इलाहाबाद : किताब महल।
5. कोठारी आयोग (1966). *शिक्षा आयोग प्रतिवेदन (1964-66)*. नई दिल्ली : भारत सरकार।
6. All India Survey on Higher Education (AISHE) (2022). *AISHE Report 2020-21*. New Delhi: Ministry of Education, Government of India.
7. Devy, G.N. (2014). *The Being of Bhasha: A General Introduction*. Hyderabad: Orient BlackSwan.
8. Mohanty, A.K. (2019). *The Multilingual Reality: Living with Languages*. Bristol: Multilingual Matters.
9. Pattanayak, D.P. (1981). *Multilingualism and Mother-Tongue Education*. Delhi: Oxford University Press.
10. Agnihotri, R.K. (2014). 'Multilinguality, education and harmony', *International Journal of Multilingualism*, 11(3), pp. 364-379.
11. Annamalai, E. (2004). 'Medium of power: The question of English in education in India', in Tollefson, J.W. & Tsui, A.B.M. (eds.) *Medium of Instruction Policies*. Mahwah: Lawrence Erlbaum, pp. 177-194.
12. Skutnabb-Kangas, T. (2000). *Linguistic Genocide in Education — or Worldwide Diversity and Human Rights?* Mahwah: Lawrence Erlbaum.
13. Graddol, D. (2010). *English Next India*. London: British Council.
14. UNESCO (1953). *The Use of Vernacular Languages in Education*. Paris: UNESCO.
15. UNESCO (2003). *Education in a Multilingual World*. Paris: UNESCO.
16. Mohanty, A.K. (2009). 'Multilingual education for social justice: Globalising the local', in Mohanty, A.K. et al. (eds.) *Multilingual Education for Social Justice*. New Delhi: Orient BlackSwan.
17. सिंह, रामशरण (2018). 'हिंदी माध्यम और उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ', *भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका*, 37(2), पृ. 45-58।
18. जैन, गिरिश्वर (2021). 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भाषा और माध्यम का प्रश्न', *शिक्षा विमर्श*, 12(1), पृ. 12-27।